

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
मुकदमा नंबर 24/2018
ऑनलाईन नंबर 2018/00040
निर्णय दिनांक 14.08.2023
तुलछी पत्नी हीराराम पुत्री दुर्गाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ जिला
बीकानेर।
-प्रार्थिनी-

बनाम

नागरमल पुत्र भंवरी पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ जिला
बीकानेर।
-अप्रार्थी-

उपस्थिति:-

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 289 तादादी 3.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 तादादी 12.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 तादादी 15.60 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 571 तादादी 5.90 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर स्व. दुर्गाराम के खातेदारी के खेत थे। स्व. दुर्गाराम के दो पुत्रियां भंवरी व तुलछी थी। भंवरी का स्वर्गवास हो गया, भंवरी के एक पुत्र नागरमल व दो पुत्रियां मीरा व हरू हुये। दुर्गाराम के स्वर्गवास के पश्चात् भंवरी व तुलछी के 1/2-1/2 हिस्सा हुआ। भंवरी की मृत्यु के पश्चात् उसका हिस्सा अप्रार्थी के नाम है। प्रार्थिनी व अप्रार्थी ने मौखिक रूप से आज से 25 वर्ष पूर्व खेत खसरा नम्बर 563 तादादी 15.60 हैक्टेयर का विभाजन किया जिसके अनुसार आधा हिस्सा दक्षिणी तरफ का प्रार्थिनी का व उत्तरी तरफ का आधा हिस्सा अप्रार्थी का हुआ, उसी अनुसार लगातार 25 वर्षों से इस खेत को कब्जा काशत करते आ रहे हैं। प्रार्थिनी ने अपने दक्षिणी हिस्से में कुआ बना लिया जिसका खर्चा प्रार्थिनी का लगा और अपने 1/2 हिस्सा दक्षिण तरफ कुआ वाला काशत करती आ रही है, बाकी खेत में अपने हिस्से का काशत करते आ रहे हैं। वादगत खेतों का मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। वादगत खेत अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में अविभाजित चल रही है। प्रार्थिनी व अप्रार्थी की संयुक्त परिवार की स्थिति समाप्त हो चुकी है। वादगत खेतों को अभी तक हिस्सा पांति के अनुसार खसरा नम्बर 563 को छोड़कर अन्य सभी खसरों का अदल-बदल कर पक्षकारों द्वारा काशत किया जाता रहा है। प्रार्थिनी अब अपना हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर करवाना चाहती है और अलग से रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवाना चाहती है, खातेदारी संयुक्त होने से प्रार्थिनी को कृषि ऋण आदि में परेशानियां आ रही है। यह है कि दिनांक 19.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थिनी ने कहा कि सहमति से रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी के अनुसार वादगत खेतों की भूमि विभाजन करवा लेवे लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा करने से इन्कार हो गया और अप्रार्थी ने प्रार्थिनी को वादगत भूमि काशत नहीं करने देने व खेतों की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की धमकियां दी। इसलिए प्रार्थिनी को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादगत खसरान भूमि स्व. दुर्गाराम के खातेदारी के खेत थे। प्रार्थिनी स्व. दुर्गाराम पुत्री है इस कारण सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थिनी के पक्ष में है व वादगत खसरान भूमि में प्रार्थिनी का 1/2 हिस्से पर कब्जा, काशत व उपयोग-उपभोग से अपूर्णाय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थिनी के पक्ष में है।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थिनी के वादगत खेत खसरा नम्बर 563 तादादी 15.60 हैक्टेयर में दक्षिणी तरफ का 1/2 हिस्सा कुआ की तरफ का व खसरा नम्बर 289 तादादी 3.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 तादादी 12.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 571 तादादी 5.90 हैक्टेयर में प्रार्थिनी का 1/2 हिस्सा में प्रार्थिनी के कब्जा काशत व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखल-अन्दाजी नहीं करें, ना ही प्रार्थिनी के हिस्से को खुर्द-बुर्द करें, ना ही प्रार्थिनी के हिस्सा भूमि में प्रवेश करे, ना ही प्रार्थिनी की हिस्सा भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय या हस्तान्तरण करें यानि अप्रार्थी ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थिनी के हितों के विपरीत हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया गया कि वादगत खेतों की खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रार्थिनी का विरासतन है तथा 1/2 हिस्सा मुझे विरासतन खातेदारी प्राप्त हुई है। वादगत खेतों का कभी भी मौखिक विभाजन नहीं हुआ है। वादगत खेतों को मैं व वादिनी बदल-बदल कर काशत करते आ रहे है। प्रार्थिनी ने जिस कुंए का हवाला दिया है, उस कुंआ में मेरा पैसा लगा है। चूंकि महिलाओं के लिये तत्समय बिजली कनेक्शन के बारे में योजना थी, इसलिये बिजली कनेक्शन सुगमता से प्राप्त हो, इसलिये प्रार्थिनी के नाम कुंआ कनेक्शन लिया गया था, कुआ का कनेक्शन प्रार्थिनी के नाम अवश्य है, जबकि उसमें पैसा मेरा ही लगा है। प्रार्थिनी का वाद गलत आधारों पर प्रस्तुत होने व कानूनी खामियों से ग्रसित होने के कारण चलने काबिल नहीं व खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2073 ग्राम राजेडू खाता संख्या 169 के अनुसार प्रार्थिनी व अप्रार्थी वादग्रस्त खसरान के सहखातेदार (प्रत्येक का 1/2 हिस्सा) है। एवं सहखातेदारान के मध्य वादग्रस्त भूमि के मध्य विभाजन दावा जैरकार है। प्रार्थिनी द्वारा वादग्रस्त खसरान में प्रार्थिनी के हिस्से कब्जा काशत में दखलंदाजी नहीं करने एवं विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने बाबत निवेदन किया गया है।

अतः प्रार्थिनी के सहखातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी के पक्ष में पाया जाता है एवं वादग्रस्त खसरान का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय/हस्तान्तरण की स्थिति में प्रार्थिनी को अपूरणीय क्षति संभावित है, अतः चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि अविभाजित पैतृक कृषि भूमि है, अस्थाई निषेधाज्ञा का उद्देश्य मूलवाद की विषयवस्तु को सुरक्षित बनाए रखना है। अतः वादिनी के हिस्से तक की वादग्रस्त भूमि को सुरक्षित रखते हुए अप्रार्थीगण तावाद वादग्रस्त भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करें। तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

आदेश आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्री इंदूरगढ़ (विभागाध्यक्ष)